

Daily Current Affairs

Date : 27 May, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान वन विभाग और TACO के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
2.	CETP स्थापना की हैम (Hybrid Annuity Model) आधारित योजना लागू
3.	BSF का प्रहरी सम्मेलन : सांचू पोस्ट (बीकानेर)
4.	मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान - 2.0
5.	IIT जोधपुर और मसाई स्कूल के मध्य प्रौद्योगिकी आधारित साझेदारी
6.	मोठ बीन अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए CAZRI को पुरस्कार
7.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. ओलम्पियन श्यामलाल मीणा का निधन 2. डॉ. मंजू बाघमार : 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' के अवॉर्ड के लिए चयनित 3. IAS नीलम मीणा : पश्चिम बंगाल की नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी 4. अल्ट्रा मैराथन धावक अमर सिंह देवदा
8.	पद्म पुरस्कार 2026
9.	नौतपा
10.	16वां वित्त आयोग तथा वित्तीय हस्तांतरण
11.	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)
12.	बाल श्रम
13.	पैमाना (PAIMANA) पोर्टल
14.	मैकफिन मार्ट एवं ग्रामीण उद्यमों का आधुनिकीकरण (MoRE) पहल
15.	ओरेश्रिक मिसाइल
16.	वाई-फाई 7

--1--



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR



राजस्थान परिदृश्य



राजस्थान वन विभाग और TACO के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान वन विभाग और द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन (TACO) के मध्य सरिस्का टाइगर रिज़र्व (अलवर) में 'नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर (NIC)' स्थापित करने संबंधी एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

राजस्थान वन विभाग

सरिस्का में इको-टूरिज्म और वन्यजीव संरक्षण को मिलेगा नवाचार और आधुनिक सुविधाओं का संबल



अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिज़र्व में इको-टूरिज्म और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अत्याधुनिक इंटरप्रिटेशन सेंटर एवं कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा।

इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजस्थान वन विभाग द्वारा श्री अनिल अग्रवाल फाउंडेशन एवं शाइन फाउंडेशन के साथ एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे संरक्षण, जागरूकता और सतत पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

--:2:--



मुख्य बिन्दु:

- नव-स्थापित सेंटर का नाम अनिल अग्रवाल के दिवंगत पुत्र अग्निवेश अग्रवाल के नाम पर 'अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर (NIC)' रखा जाएगा।
- सरिस्का टाइगर रिज़र्व में प्रस्तावित नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर वन्यजीव संरक्षण जागरूकता, पर्यावरण शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित स्थान होगा।
- यह केंद्र जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी स्थिरता तथा वन्यजीवों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के महत्त्व को समझने में सहायता करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

- **शाइन फाउंडेशन के साथ MoU :** राजस्थान वन विभाग ने सरिस्का टाइगर रिज़र्व में इको-टूरिज्म और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 'शाइन फाउंडेशन' के साथ भी एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत सरिस्का में लगभग ₹1.04 करोड़ की लागत से एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा।
- **राजस्थान बाघ संरक्षण फाउंडेशन की चौथी बैठक :** जयपुर स्थित अरण्य भवन में आयोजन। इस बैठक में वर्ष 2026-27 के दौरान प्रदेश के विभिन्न टाइगर रिज़र्व में कराए जाने वाले विकास और संरक्षण कार्यों के लिए ₹6,493 लाख की वार्षिक कार्य योजना (APO) को स्वीकृति प्रदान की गई।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान में स्थित टाइगर रिज़र्व :-

क्रमांक	टाइगर रिज़र्व	घोषणा का वर्ष	शामिल जिले
1.	रणथंभौर टाइगर रिज़र्व	1973	सवाई माधोपुर, करौली, बूँदी, टोंक
2.	सरिस्का टाइगर रिज़र्व	1978	अलवर, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़
3.	मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व	2013	कोटा, बूँदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़
4.	रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व	2022	बूँदी, कोटा
5.	धौलपुर-करौली टाइगर रिज़र्व	2023	धौलपुर, करौली

CETP स्थापना की हैम (Hybrid Annuity Model) आधारित योजना लागू



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु 'CETP स्थापना की Hybrid Annuity Model' आधारित नई योजना को लागू करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए।

सीईटीपी स्थापना की हैम मॉडल आधारित नई योजना लागू

राज्य सरकार का उद्योगों को संबल और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला

सीईटीपी की स्थापना के लिए मिलेगा 150 करोड़ रुपये तक अनुदान

आधुनिक तकनीक 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' वाले प्लांट लगेंगे

PRE-TREATMENT ZERO LIQUID DISCHARGE PLANT

RajGovOfficial

--:4:--



मुख्य बिन्दु:

- **अनुदान :** इस योजना के तहत प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम ₹150 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
- **वित्तीय सहायता का वर्गीकरण :** CETP के प्रभावी संचालन के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर अनुदान दिया जाएगा। इसके तहत कार्य के चरणों के अनुसार भुगतान किया जाएगा, 60 प्रतिशत अनुदान 20-20 प्रतिशत की तीन किस्तों में और 20 प्रतिशत राशि 20 वर्षों में उपलब्ध कराई जाएगी।
- **वित्तीय सहायता हेतु अधिकृत एजेंसी :** RIICO औद्योगिक क्षेत्र में RIICO एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) द्वारा तथा नॉन- RIICO औद्योगिक क्षेत्रों में राजस्थान सरकार एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- वर्तमान में प्रदेश में अधिकतर औद्योगिक इकाइयों में अपशिष्ट जल का प्रबंधन व्यक्तिगत एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) या क्लस्टर-स्तर के CETP के माध्यम से किया जाता है, लेकिन इस नई योजना के तहत आधुनिक तकनीक 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' वाले प्लांट लगने से एफ्लुएंट वाटर का पुनः उपयोग किया जा सकेगा।
- **प्रावधान :** इस योजना के तहत CETP के निर्माण और संचालन के लिए क्लस्टर की उद्योग इकाइयों द्वारा एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनानी होगी।

कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP)

- कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) एक केंद्रीकृत सुविधा है, जिसे एक विशिष्ट औद्योगिक समूह के भीतर स्थित कई उद्योगों से अपशिष्ट जल को एकत्र करने, उपचारित करने और सुरक्षित रूप से निर्वहन या पुनर्चक्रित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

उपचार प्रक्रिया:

- **प्रारंभिक उपचार :** यह बड़े ठोस मलबे और रेत आदि को छानकर अलग करता है और आने वाले अपशिष्ट जल के pH (Potential of Hydrogen) और तापमान को नियंत्रित करता है।
- **प्राथमिक उपचार :** इसमें अवसादन और जमाव जैसी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके ठोस पदार्थों को अलग किया जाता है और तेल और ग्रीस की मात्रा को कम किया जाता है।
- **द्वितीयक (जैविक) उपचार :** कार्बनिक संदूषकों को तोड़ने और जैविक ऑक्सीजन माँग (BOD) और रासायनिक ऑक्सीजन माँग (COD) को कम करने के लिए विशेष बैक्टीरिया और जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है।
- **तृतीयक उपचार :** उन्नत निस्पंदन, कार्बन अवशोषण और कीटाणुशोधन पानी को शुद्ध करने के लिए ताकि यह सुरक्षित निर्वहन या पुनः उपयोग मानकों को पूरा कर सके।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

- **राजस्थान इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट पॉलिसी :** राजस्थान मंत्रिमण्डल द्वारा 22 मई, 2026 को अनुमोदित इस पॉलिसी के माध्यम से RIICO एवं नॉन-RIICO क्षेत्रों में CETP (Common Effluent Treatment Plant) की स्थापना के लिए नई योजनाएँ लाई जायेंगी तथा नए इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्कों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- **CETP संबंधी अन्य योजना :** उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (राजस्थान) द्वारा राज्य में औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु संचालित 'एकीकृत CETP की स्थापना और मौजूदा CETP के उन्नयन के लिए संशोधित योजना' के तहत एकमुश्त अनुदान देने का प्रावधान है।
- इसके तहत दिए जाने वाले अनुदान को परियोजना लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही, नॉन-RIICO आद्योगिक क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है।

BSF का प्रहरी सम्मेलन : सांचू पोस्ट (बीकानेर)

चर्चा में क्यों?

- 26 मई, 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बीकानेर स्थित सीमा सुरक्षा बल (BSF) की सांचू पोस्ट पर 'प्रहरी सम्मेलन' का आयोजन किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई-लोकार्पण किया।
- वर्तमान में, राजस्थान में BSF की सीमा चौकियों पर महिला सैनिकों के लिए ₹40 करोड़ की लागत से 79 बैरक स्वीकृत किए गए हैं।

Daily Current Affairs

Date : 27 May, 2026



- 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' की प्रगति की समीक्षा बैठक : केन्द्रीय गृहमंत्री ने बीकानेर में सीमावर्ती पाँच जिलों (बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और फलौदी) के जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों (SPs) के साथ बढ़ते सीमा पार ड्रग्स/हथियार तस्करी और 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' की प्रगति को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स (सीमा सुरक्षा बल - BSF):

- स्थापना : 1 दिसंबर, 1965
- वर्तमान महानिदेशक : प्रवीण कुमार (IPS)
- ध्येय वाक्य : जीवन पर्यंत कर्तव्य।
- मंत्रालय : गृह मंत्रालय।

मुख्य उद्देश्य :

- शांतिकाल में भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना।
- सीमा पार होने वाले अपराधों, जैसे - घुसपैठ, तस्करी, और अवैध प्रवेश को रोकना।
- युद्ध के समय भारतीय सेना की सहायता करना।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना।

--8--

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान - 2.0



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA) 2.0 के तहत जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन कार्यों को गति देने के उद्देश्य से द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए ₹688.28 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की।



राजस्थान सरकार
जल ग्रहण विकास एवं
भू-संरक्षण विभाग



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

राजस्थान बजट 2024



मुख्यमंत्री
जल स्वावलंबन
अभियान

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत
11 हजार 200 करोड़ रुपये की लागत से आगामी चार वर्षों
में राजस्थान के 20 हजार गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग
स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे।



--:9::--



मुख्य बिन्दु:

- अभियान के द्वितीय चरण के लिए जल संरक्षण उपकर निधि से ₹488.28 करोड़ तथा तृतीय चरण के लिए राज्य निधि प्रावधान से ₹200 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
- राज्य सरकार द्वारा इस अभियान के तहत अब तक विभिन्न चरणों में ₹988.28 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 (MJSA 2.0)

- **घोषणा** : राजस्थान बजट 2024-25 में।
- **शुरुआत** : फरवरी, 2024 में राज्य सरकार द्वारा।
- **उद्देश्य** : राजस्थान में अधिकतम वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना।
- इस अभियान के अन्तर्गत नए एनीकट, खेत तालाब, मिनी परकोलेशन टैंक (MPT), सब सरफेस बैरियर (SSB) का निर्माण और पुराने जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत आदि का कार्य किया जाता है।
- वर्ष 2024 से 2028 के दौरान MJSA 2.0 के तहत राज्य के 20,000 गाँवों में 5,00,000 जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA)

- **शुरुआत** : 27 जनवरी, 2016 को झालावाड़ ज़िले के गरदान खेड़ी गाँव से इस अभियान का शुभारंभ किया गया।
- **उद्देश्य** : ग्रामीण क्षेत्रों में जल की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना, अकाल के समय जल की उपलब्धता एवं जल की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करना।
- **नोट** : जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश भर के कुल 193 अत्यधिक जल दोहन वाले जिलों में राजस्थान के 29 जिले शामिल हैं। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश (38 जिले) के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है।

IIT जोधपुर और मसाई स्कूल के मध्य प्रौद्योगिकी आधारित साझेदारी



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर ने परिणाम-आधारित शिक्षा मंच मसाई स्कूल के साथ दो नए अंतःविषयक डिग्री कार्यक्रम शुरू करने हेतु रणनीतिक सहयोग स्थापित किया।



मुख्य बिन्दु:

- इस साझेदारी के तहत - BS इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी तथा MBA टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं।
- **BS इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी** : इसे कक्षा 12वीं के बाद सभी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है, जिससे गैर-विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी IIT से संबद्ध डिग्री प्राप्त करना संभव होगा।

-:11:-

Daily Current Affairs

 Date : 27 May, 2026



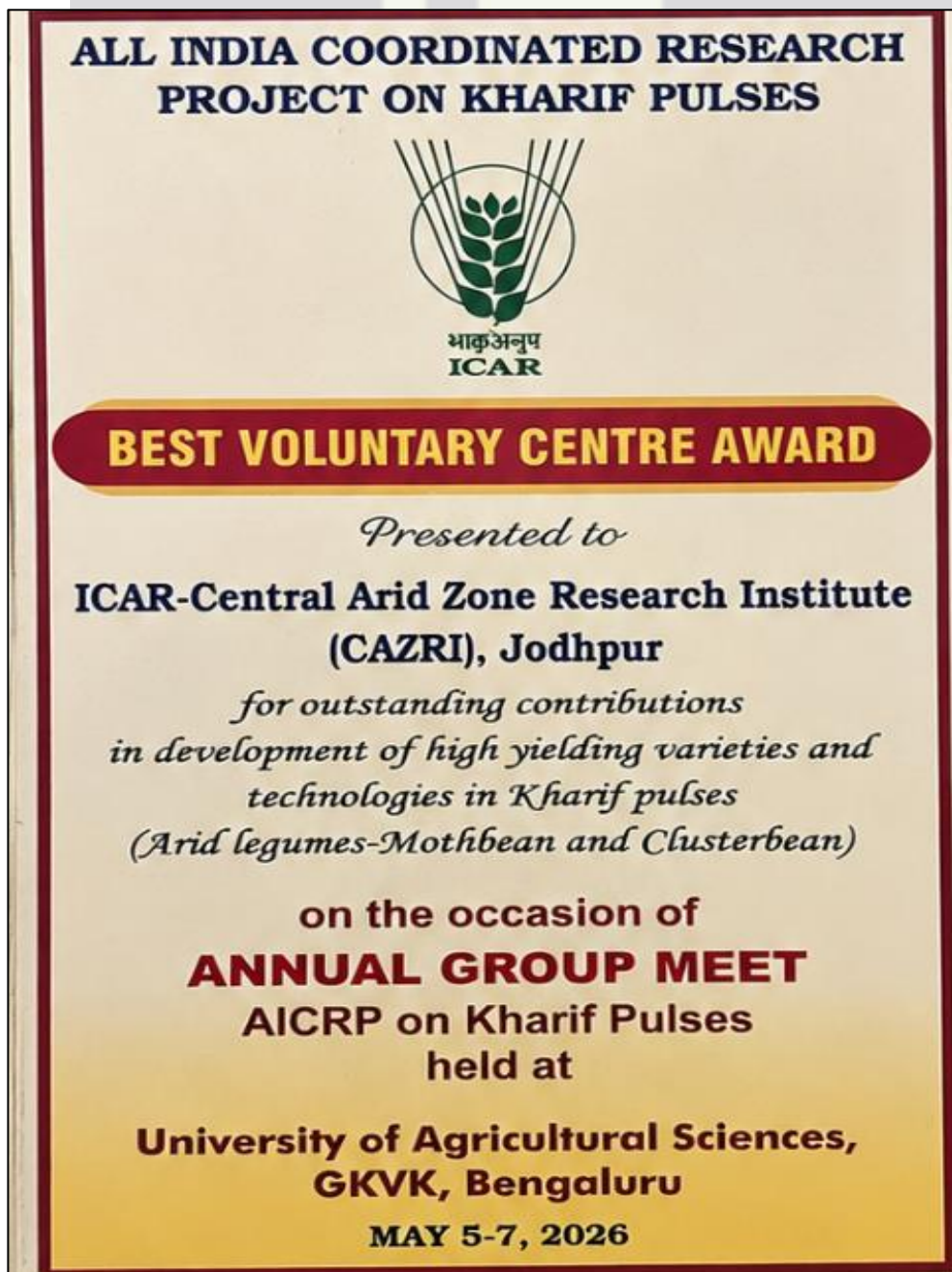
- इस कार्यक्रम में एक क्वालिफायर टेस्ट के माध्यम से प्रवेश होगा। 141 क्रेडिट वाले इस पाठ्यक्रम में आठ सेमेस्टर शामिल होंगे, जिनमें तकनीक, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान का संतुलित समावेश रहेगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप, इस कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष के बाद एग्जिट विकल्प भी उपलब्ध होंगे।
- **MBA टेक्नोलॉजी प्रोग्राम :** इसे विभिन्न उद्योगों में कार्यरत पेशेवरों के लिए तैयार किया गया है, जो तकनीक-आधारित व्यावसायिक परिवेश की समझ को सुदृढ़ करना तथा नेतृत्व एवं रणनीतिक निर्णय क्षमता को विकसित करना चाहते हैं।
- 66-क्रेडिट वाले इस कार्यक्रम में कार्य-एकीकृत परियोजना के साथ-साथ रणनीतिक प्रबंधन, डिजिटल एंटरप्राइज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उभरती प्रौद्योगिकियाँ तथा उत्पाद-केंद्रित शिक्षण को शामिल किया गया है।
- इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को आधुनिक तकनीक-आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना है।
- इन नए कार्यक्रमों को तकनीकी दक्षता, प्रबंधन विशेषज्ञता तथा मानवीय एवं सामाजिक दृष्टिकोण को एकीकृत शैक्षणिक ढाँचे में समाहित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

-:12:-

मोठ बीन अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए CAZRI को पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- ICAR - केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर को हाल ही में मोठ बीन अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'सर्वश्रेष्ठ केन्द्र पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।



-:13:-



मुख्य बिन्दु:

- काजरी को यह पुरस्कार भारतीय गर्म शुष्क क्षेत्रों के लिए मोठ और ग्वार फसलों के आनुवंशिक सुधार और उत्कृष्ट अनुसंधान कार्यों के लिए मिला है।
- **सम्मान समारोह** : खरीफ दलहन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRP) की वार्षिक समूह बैठक, बेंगलुरु में।
- **6 नई किस्में** : काजरी ने वर्ष 2024 से 2026 की अल्पावधि में मोठ बीन की छह उच्च उपज वाली और सूखा-प्रतिरोधी किस्में (काजरी मोठ - 4 से काजरी मोठ - 9) विकसित की।
- मोठ एक अत्यधिक जलवायु-प्रतिरोधी दलहन है, जिसकी खेती मुख्य रूप से गर्म शुष्क क्षेत्रों के कम वर्षा वाले इलाकों में की जाती है।
- नई विकसित किस्मों में लंबे समय तक सूखे और कभी-कभी अधिक वर्षा दोनों स्थितियों में वांछनीय अनुकूलन क्षमता और विकासात्मक लचीलापन है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI), जोधपुर

- **स्थापना**: वर्ष 1959 में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अंतर्गत।
- **मुख्यालय** : जोधपुर।
- **क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र** : बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जालौर और भुज (गुजरात) में।
- **मुख्य उद्देश्य** : शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों (Arid & Semi-Arid Regions) में टिकाऊ कृषि, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं ग्रामीण आजीविका सुधार हेतु अनुसंधान करना।

प्रमुख कार्यक्षेत्र :

- **भूमि एवं जल संरक्षण** - मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव रोकना और जल का समुचित उपयोग।
- **वनस्पति अनुसंधान** - कम पानी वाली फसलें, चारा उत्पादन और बागवानी पद्धतियों का विकास।
- **पशुपालन अनुसंधान** - ऊँट, भेड़, बकरी आदि शुष्क क्षेत्र के पशुओं की नस्ल सुधार व प्रबंधन।
- **प्रौद्योगिकी विकास** - मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए सिंचाई तकनीक, वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा आधारित उपकरण।
- **जलवायु अनुसंधान** - मरुस्थल में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	ओलम्पियन श्यामलाल मीणा का निधन ■ भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता श्यामलाल मीणा का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ■ जन्म : 4 मार्च, 1965 को बाँसवाड़ा जिले के केवड़िया में। ■ वर्ष 1987 में कोलकाता में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले वे राजस्थान के पहले तीरंदाज बने। ■ उन्होंने वर्ष 1988 के सियोल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ■ खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1989 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया।
2.	डॉ. मंजू बाघमार : 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' के अवॉर्ड के लिए चयनित ■ हाल ही में, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार को लंदन की प्रतिष्ठित संस्था 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' द्वारा अंतरराष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया। ■ उन्हें 26 जून, 2026 को ब्रिटेन की संसद के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में आयोजित होने वाले 10वें अवॉर्ड समिट में सम्मानित किया जाएगा। ■ डॉ. बाघमार ने अपने संवेदनशील नेतृत्व, उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों तथा समाज के प्रति समर्पण से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाई है।

3.	IAS नीलम मीणा : पश्चिम बंगाल की नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी ■ सवाई माधोपुर के बामनवास की निवासी और पश्चिम बंगाल कैडर की IAS अधिकारी नीलम मीणा को 25 मई, 2026 को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। ■ नीलम ने IAS मनोज कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है, जिन्हें पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
4.	अल्ट्रा मैराथन धावक अमर सिंह देवदा ■ जयपुर के चीथवाड़ी गाँव निवासी अमर सिंह देवदा ने हाल ही में जापान के हिरोसाकी शहर में आयोजित 'IAU 24-अवर एशिया एंड ओशिनिया चैंपियनशिप 2026' में स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। ■ उन्होंने 24 घंटे की रेस में लगातार दौड़ते हुए 282.881 किलोमीटर की दूरी तय की और व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता।





राष्ट्रीय परिदृश्य



पद्म पुरस्कार 2026

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- भारत की राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'नागरिक अलंकरण समारोह-I' में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए।



-:17:-



मुख्य बिन्दु:

- इस वर्ष कुल 131 पुरस्कार दिए जाने हैं। इनमें 19 महिलाएं, विदेशी/NRI/PIO/OCI श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार-प्राप्तकर्ता शामिल हैं। पुरस्कार विजेताओं में 2 युगल मामले भी हैं, जिन्हें एक माना गया है।

पद्म पुरस्कार

- **शुरुआत:** पुरस्कारों का गठन 1954 ई. में हुआ। ये देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं।
- **पुरस्कार प्रदानकर्ता:** भारत के राष्ट्रपति द्वारा तीन श्रेणियों में पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं:
 - **पद्म विभूषण:** असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए।
 - **पद्म भूषण:** उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए।
 - **पद्म श्री:** किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए।
- **घोषणा:** प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की जाती है (कुछ अपवाद वर्षों को छोड़कर)।
- **पात्रता:** नस्ल, पेशा, पद या लैंगिक भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी सहित सरकारी कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं होते। हालांकि, डॉक्टर और वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- **सामान्यतः:** यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, लेकिन अत्यंत विशिष्ट मामलों में इसे मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है।
- **पुरस्कार विजेताओं की संख्या-सीमा:** एक वर्ष में कुल 120 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जा सकते (मरणोपरांत और विदेशी श्रेणियों को छोड़कर)।
- **पुरस्कार विजेताओं का चयन:** प्रधान मंत्री द्वारा गठित 'पद्म पुरस्कार समिति' प्रत्येक वर्ष विजेताओं का चयन करती है।

Daily Current Affairs



Date : 27 May, 2026



पद्म विभूषण 2026 के विजेताओं की सूची

नाम	क्षेत्र
श्री धर्मेन्द्र सिंह देओल (मरणोपरांत)	कला (सिनेमा)
श्री के. टी. थॉमस	सार्वजनिक मामले (उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश)
सुश्री एन. राजम	कला (संगीत): वायलिन वादक, जिन्हें 'सिंगिंग वायलिन' कहा जाता है।
श्री पी. नारायणन	साहित्य और शिक्षा
श्री वी. एस. अच्युतानंदन (मरणोपरांत)	सार्वजनिक मामले (केरल के पूर्व मुख्यमंत्री)





भूगोल एवं भू-विज्ञान



नौतपा

(स्रोत: Economic times)



चर्चा में क्यों?

- नौतपा के दौरान उत्तर भारत में मौसम की सबसे गर्म अवधि की शुरुआत हुई।



मुख्य बिन्दु:

नौतपा

- यह हिंदू कैलेंडर में एक पारंपरिक नौ-दिवसीय मौसमी चरण है जो गर्मियों में लू की चरम अवधि को दर्शाता है।
- नौतपा का उल्लेख सूर्य सिद्धांत जैसे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में मिलता है।
- यह नौ और तपा (गर्मी) शब्दों से मिलकर बना है जो तब शुरू होता है जब सूर्य मई के अंत में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है।
- इस वर्ष नौतपा 25 मई से 2 जून तक रहने की संभावना है और यह एक प्रबल अल नीनो के लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभावों के साथ संयोग कर रहा है।
- एल नीनो का अर्थ उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतही जलधाराओं के गर्म होने से है, जिसके कारण भारत में प्रायः अधिक गर्मी पड़ती है।



आर्थिक घटनाक्रम

16वां वित्त आयोग तथा वित्तीय हस्तांतरण

(स्रोत: The Hindu)

चर्चा में क्यों?

- यह चिंता सामने आई है कि क्या वित्त आयोग द्वारा राज्यों को किए जाने वाले हस्तांतरण, केंद्र की बढ़ती व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ राज्यों के बीच वित्तीय समानता को उचित रूप से संतुलित कर पा रहे हैं।

मुख्य बिन्दु:

16वें वित्त आयोग (2026-31):

- इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। डॉ. अरविंद पनगढ़िया इसके अध्यक्ष हैं।

मुख्य सिफारिशें:

- केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% पर अपरिवर्तित रखी गई है।
- 5 वर्षों में स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन के लिए ₹9.47 लाख करोड़ की कुल अनुदान सहायता का प्रावधान है।
- राजस्व-घाटा आधारित, क्षेत्रक-विशिष्ट और राज्य-विशिष्ट अनुदानों को समाप्त कर दिया गया है।

वित्तीय हस्तांतरण और समानता से जुड़ी चुनौतियाँ:

- **विभाज्य कर पूल में कमी:** साझा न किए जाने वाले उपकर और अधिभार बढ़ने से राज्यों को उपलब्ध वास्तविक धनराशि कम हो जाती है।
- **समानता बनाम प्रदर्शन:** आय विषमता को अधिक महत्त्व देने से कम विकसित राज्यों को अधिक लाभ मिलता है। विकसित राज्यों को लगता है कि उन्हें आर्थिक विकास और जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित किया जा रहा है।

- **सशर्त हस्तांतरण:** विशेष उद्देश्यों के लिए दिए गए अनुदान राज्यों की खर्च करने की स्वायत्तता को सीमित कर सकते हैं।
- **ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण में असंतुलन:** स्वास्थ्य-देखभाल, शिक्षा और कल्याण जैसे क्षेत्रकों में व्यय जैसी बड़ी जिम्मेदारी राज्यों के पास होती है, लेकिन उनके पास कर लगाने की सीमित शक्तियाँ होती हैं।
- उदाहरण के लिए, पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी 'विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)' में 40% लागत राज्यों को वहन करनी पड़ेगी।
- राजस्व-घाटा आधारित अनुदान की समाप्ति।

समाधान

- विभाज्य कर पूल को बढ़ाने के लिए उपकर और अधिभार को तर्कसंगत बनाना चाहिए। साथ ही, व्यापक परामर्श के माध्यम से 'सहकारी संघवाद' को बढ़ावा देना चाहिए।
- वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन और समानता के बीच संतुलन बनाने हेतु मानदंडों को और बेहतर बनाना चाहिए।
- विकास के मामले में राज्यों की स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के लिए पूर्वानुमान योग्य और बिना शर्त वित्तीय हस्तांतरण किए जाएं।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के 'आधार वर्ष संशोधन' पर तकनीकी सलाहकार समिति की रिपोर्ट जारी की।



मुख्य बिन्दु:

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

- IIP एक समग्र संकेतक है, जो किसी आधार वर्ष की तुलना में एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के समूह के उत्पादन की मात्रा में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है।
- **जारीकर्ता:** MoSPI के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)।

--:23:-

Daily Current Affairs



Date : 27 May, 2026



- **कवरेज:** तीन क्षेत्रक- विनिर्माण (77.63%), खनन (14.37%), बिजली (7.99%)।
- **आधार वर्ष:** 2011-12 (नई श्रृंखला में यह 2022-23 होगा)।

IIP की नई श्रृंखला में प्रमुख परिवर्तन:

- **शामिल क्षेत्रकों का विस्तार:** इसमें लघु खनिज, दुर्लभ मृदा खनिज, गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं।
- नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली के लिए अलग-अलग सूचकांक।
- खनन और उत्खनन क्षेत्र को तीन उप-सूचकांकों में विभाजित किया गया है: ईंधन खनिज, धात्विक खनिज, और अधात्विक खनिज।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES





समाजशास्त्र



बाल श्रम

(स्रोत: News on air)



चर्चा में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में बाल श्रम पर सख्त रोक की आवश्यकता पर बल देते हुए सरकार को नोटिस जारी किया।



मुख्य बिन्दु:

बाल श्रम के विरुद्ध प्रावधान

संवैधानिक:

- अनुच्छेद 24: यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों, खदानों या खतरनाक व्यवसायों में नियोजन पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 39: यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की कोमल उम्र का दुरुपयोग न हो।
- अनुच्छेद 23: यह अनुच्छेद मानव तस्करी, बेगार (जबरन श्रम) आदि पर रोक लगाता है।

विधिक प्रावधान:

- बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) 1986 (2016 में संशोधित): यह अधिनियम सभी व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों और खतरनाक व्यवसायों में किशोरों (14-18 वर्ष) के नियोजन पर रोक लगाता है।
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

📦 योजनाएँ एवं नीतियाँ 📦

पैमाना (PAIMANA) पोर्टल

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- पैमाना पोर्टल केंद्रीय क्षेत्रक की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी को सुदृढ़ करता है।



मुख्य बिन्दु:

- यहाँ पैमाना (PAIMANA) से आशय है; राष्ट्र-निर्माण हेतु परियोजना मूल्यांकन, अवसंरचना निगरानी और विश्लेषण।
- यह पोर्टल अप्रैल, 2026 से लगभग ₹43 लाख करोड़ मूल्य की 1,981 अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी कर रहा है।

PAIMANA पोर्टल

- **उद्देश्य:** ₹150 करोड़ और उससे अधिक राशि की केंद्रीय क्षेत्रक की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल के रूप में कार्य करना।

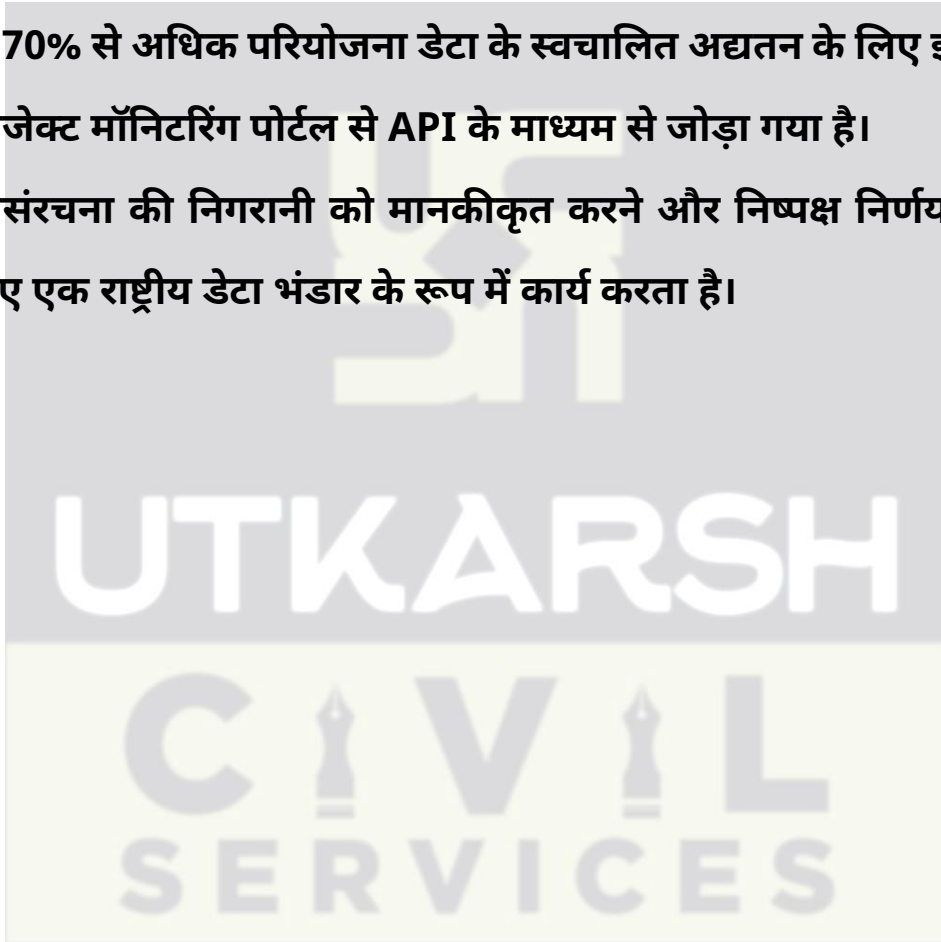
-:26:-

Daily Current Affairs

 Date : 27 May, 2026



- केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा संचालित।
- इसने OCMS-2006 (ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली) का स्थान लिया है।
- **मुख्य विशेषताएं:** व्यवस्थित निगरानी के लिए "एक डेटा, एक प्रविष्टि" सिद्धांत पर कार्य करता है।
- **एकीकरण:** 70% से अधिक परियोजना डेटा के स्वचालित अद्यतन के लिए इसे DPIIT के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल से API के माध्यम से जोड़ा गया है।
- **महत्त्व:** अवसंरचना की निगरानी को मानकीकृत करने और निष्पक्ष निर्णय लेने में मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटा भंडार के रूप में कार्य करता है।



मैकफिन मार्ट एवं ग्रामीण उद्यमों का आधुनिकीकरण (MoRE)

पहल

(स्रोत: News on air)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में सिडबी के 37वें स्थापना दिवस पर MSME प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रमुख पहलें शुरू की।

मुख्य बिन्दु:

- SIDBI एक सांविधिक निकाय है। यह MSME क्षेत्रक के संवर्धन, वित्त-पोषण और विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है।

मैकफिन मार्ट (MachFin Mart)

- यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह MSME को आसानी से आधुनिक मशीनरी खरीदने में मदद करता है।
- यह प्लेटफॉर्म MSMEs को सत्यापित उपकरणों को देखने, कीमतों की तुलना करने तथा त्वरित और डिजिटल तरीके से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करता है।

ग्रामीण उद्यमों का आधुनिकीकरण (MoRE)

- यह पहल स्थानीय और जमीनी स्तर के व्यवसायों को लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- इसका उद्देश्य अगले तीन वर्षों में 10,000 ग्रामीण और हस्तशिल्प उद्यमों का आधुनिकीकरण करना है।



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



ओरेश्निक मिसाइल

(स्रोत: HINDUSTAN TIMES)



चर्चा में क्यों?

- रूस ने यूक्रेन के कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमले में ओरेश्निक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया।



मुख्य बिन्दु:

- ओरेश्निक एक मध्यम दूरी का हाइपरसोनिक हथियार है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह रूस की RS-26 रूबेझ प्रणाली पर आधारित है। यह परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के युद्धक हथियारों को ले जा सकता है।
- इसकी मारक क्षमता 3,000 से 5,500 किलोमीटर के बीच होने का अनुमान है, जिससे यह यूरोप के बड़े हिस्सों को निशाना बना सकता है।
- इस मिसाइल की गति मैक 10 यानी लगभग 2.5-3 किलोमीटर प्रति सेकंड होने के कारण आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों के लिए इसे रोकना लगभग असंभव है।

--:29::--

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚡

वाई-फाई 7

(स्रोत: DD NEWS)



चर्चा में क्यों?

- TP-लिंक द्वारा वाई-फाई 7 उपकरणों का स्थानीय निर्माण शुरू किए जाने के साथ भारत ने वाई-फाई 7 युग में प्रवेश कर लिया है।



मुख्य बिन्दु:

वाई-फाई 7

- वाई-फाई 7 (आधिकारिक तौर पर IEEE मानक 802.11be) वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक की अगली पीढ़ी है।
- **उद्देश्य:** अपने पूर्ववर्तियों, वाई-फाई 6 और वाई-फाई 6E की तुलना में प्रदर्शन, गति और दक्षता को बढ़ाना।

--:30:--

वाई-फाई 7 की विशेषताएँ:

- वाई-फाई 6 की तुलना में 4.8 गुना तेज गति (थ्रूपुट को 46 Gbps तक बढ़ाता है)।
- 2.4/5/6 GHz बैंड पर मल्टी-लिंक ऑपरेशन (MLO)।
- वाई-फाई 6/6E की तुलना में 4 गुना कम लैटेंसी।
- व्यापक चैनल बैंडविड्थ (एक साथ अधिक डेटा प्रसारित किया जाता है)।
- उन्नत टारगेट वेक टाइम से बिजली की खपत कम होती है और बैटरी अधिक दिनों तक चल सकती है।
- **व्यवधान से निपटने में बेहतर:** 'प्रिएम्बल पंचरिंग' से यह सुनिश्चित होता है कि चैनल के एक हिस्से में व्यवधान होने पर भी संचार जारी रहता है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES